न हो पाने के कारण विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना-अवधि के दौरान वर्ष-वार उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण कितनी राशि की अतिरिक्त हानि होने का अनुमान है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और एवंराजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-I और II, जिन्हें क्रमशः फरवरी, 1994 और अगस्त, 1994 से बड़े अनुरक्षण कार्य हेतु लिया हुआ है, को छोड़कर देश के परमाणु बिजलीघरों का वार्षिक औसत क्षमता उपयोग VIIIवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान क्रमशः 60%, 40%, 47 और 60% था, तथा चालू वर्ष में नवम्बर, 1996 के अंत तक यह 60% था। वर्ष 1993-94 के दौरान क्षमता गुणक मुख्ततः इस कारण कम रहे क्योंकि टर्बाइन में आग लगने की घटना के बाद नरोरा यूनिट-I को पुनःस्थापन के लिए लम्बे समय तक बंद कर दिया गया था और इसके फलस्वरूप नरोरा-II, मद्रास यूनिट-I और II तथा ककरापार-I को टर्बाइनों तथा सहयोगी तंत्रों का निरीक्षण करने और उनमें संशोधन करने के लिए बंद कर दिया गया था। काम कर रहे रिएक्टरों के कार्य-निष्पादन में पिछले दो वर्षों से उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। 1995-96 और 1996-97 (नवम्बर तक) के दौरान उपलब्धता गुणक क्रमशः 68% और 65% हासिल किए गए। उत्पादन करने वाले नए यूनिटों नामतः एन०ए०पी०एस०-I और II , आर०ए०पी०एस०-I और II ने 1995-96 में क्रमशः 75%, 81%, 73% और 85% तथा 1996-97 में (नवम्बर तक) 73%, 74%, 85% और 87% वार्षिक उपलब्धता गुणक हासिल किए।

(ग) और (घ) परमाणु बिजलीघरों से बिजली का विक्रय करने के लिए यूनिट ऊर्जा प्रभार 62.8% के गणकीय क्षमता गुणक के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और यह वास्तविक क्षमता उपयोग पर निर्भर नहीं करता है। जब यूनिट मानकीय क्षमता गुणक से अधिक पर कार्य करते हैं तब लाभ की गुंजाइश अधिक होगी और इसी तरह इसके विपरीत होगा।

आठवीं योजनावधि के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के प्रचालन परिणाम नीचे दिए अनुसार हैं:—

1992-93	निवल लाभः 72 करोड़ रुपए
1993-94	निवल हानिः 146 करोड़ रुपए
1994-95	निवल लाभः 134 करोड़ रुपए
1995-96	निवल लाभः 152 करोड़ रुपए
1996-97	निवल लाभः 186 करोड़ रुपए

*(अनंतिम, नवम्बर, 1996 के अंत तक)

अनंतिम आंकड़ों के आधार पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने 1996-97 के दौरान नवम्बर, 1996 के अंत तक 186 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार VIII वीं योजनावधि के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने अब तक कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए निवल लाभ अर्जित किया है।

Energy Shortage in Eastern Region

*308. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present overall energy shortage in the Eastern Region as a whole and Bihar in particular, with details thereof; and

(b) the measures being taken by Government to improve the availability of power in the Eastern Region, particularly in Bihar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENGERY SOURCES (DR S. VENUGOPALACHARI): (a) The energy shortage in the Eastern Region and Bihar during October, 1996 was 7% and 23.8% respesctively. During the same period the peaking shortage in the Eastern Region and Bihar was 20.4% and 41.2% respectively.

(b) The following important measures are taken to improve the availability of power in Eastern Region and Bihar:

(i) Renovation and Modernisation of Thermal Plants for impriving the plant load factor;

(ii) Capacity addition to meet peaking shortage;

(iii) demand management;

(iv) Energy conservation; and

(v) Reduction in Transmission & Distribution losses.

People below the Poverty Line

*309. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether percentage of people below the poverty line has been steadily going down during the period from 1991 to 1996;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) whether it is a fact that Government do not have any authentic data regarding the people below the poverty line in rural and urban areas;

(d) if so, the regions therefor; and

(e) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) The Planning Commission estimates incidence of poverty at national and state levels based on quinquennial consumer expenditure survey data of National Sample Survey (NSS). The latest estimates of poverty based on such survey relate to the year 1987-88 (NSS on 43rd round). The consumer expenditure survey results of NSS 50th round relating to the year 1993-94 are under process. As such, it is not possible to draw any conclusion about the trend in poverty between 1991 and 1996.

(c) No, Sir. The estimates of poverty in any year is worked out from the distribution of persons in different expenditure groups given by the quinquennial NSS data on consumer expenditure, and the poverty line. The information on distribution of persons are available at regular intervals of five years and the poverty lines are worked out from the price indices which are available annually.

(d) and (e) Does not arise.

पंजाब में कृषि क्षेत्र के लिए निधियों का आवंटन

*310. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कृषि तथा इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए पंजाब को कितनी राशि का आवंटन किया गया तथा यह राशि कुल योजना परिव्यय से कितने प्रतिशत अधिक है; और

(ख) इस राज्य में कृषि के विकास और तीव्र प्रगति के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ):

(क) 1994-95 से 1996-97 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए पंजाब द्वारा किए गए आवंटन निम्नानुसार हैं:

वर्ष	परिव्यय (लाख रु॰ में)	राज्य के कुल परिव्यय में प्रतिशत हिस्सा
1994-95	8955.00	6.18
1995-96	10789.00	6.44
1996-97 (प्रस्तावित)	10478.69	5.64

(ख) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए पंजाब की राज्य सरकार राज्य सैक्टर के अन्तर्गत कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है, राज्य सरकार के प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक केन्द्रीय सैक्टर तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमें भी कार्यन्वित की जा रही हैं ताकि कृषि का तीव्र विकास हो सके।